हिराजी तोलाजी बागवान

बनाम

शकुंतला

16 जनवरी, 1990।

[के. एन. साइकिया और पी. बी. सावंत, जे. जे.]

बॉम्बे किरायेदारी और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, 1958: धारा 38 और 46-विभाजन द्वारा 1 अगस्त, 1953 के बाद भूमि का हस्तांतरण-क्या हस्तांतरणकर्ता को समाप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

अपीलार्थी बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स के तहत विवादित कृषि भूमि का एक संरक्षित पट्टेदार या किरायेदार था।

(विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, 1958। प्रत्यर्थी 29 जून, 1959 को भूमि की मकान मालकिन बन गई, जब उसके पिता ने एक ओर अपनी और दूसरी ओर अपनी पत्नी और प्रतिवादी सहित उसकी दो नाबालिग बेटियों के बीच अपनी पैतृक भूमि का विभाजन कर दिया। यह प्रतिवादी के पिता द्वारा प्रभावित तीसरा विभाजन था, जिन्होंने पहले भी दो बार एक ही भूमि का विभाजन किया था।

1962 में किसी समय, प्रत्यर्थी ने चूक के आधार पर वाद भूमि के कब्जे की वसूली के लिए अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। तहसीलदार ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि

प्रत्यर्थी मकान मालकिन नहीं था क्योंकि विचाराधीन विभाजन अवैध था। अपील में डिप्टी कलेक्टर ने इस निर्णय की पुष्टि की और महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी के संशोधन को खारिज कर दिया। तीनों प्राधिकरणों के उपरोक्त निर्णय के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में

नीचे, उच्च न्यायालय ने विभाजन की वैधता में निवेश के लिए मामले को तहसीलदार को भेज दिया। रिमांड पर तहसीलदार ने माना कि 29 जून, 1959 को हुआ विभाजन फर्जी था। इसके बाद, एक अलग कार्यवाही में महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण ने माना था कि उक्त विभाजन बाध्यकारी था। इसलिए, तहसीलदार के फैसले के खिलाफ अपील में, उप-कलेक्टर ने राजस्व न्यायाधिकरण के उक्त फैसले को कम करते हुए विभाजन को वैध ठहराया और प्रतिवादी के निष्कासन के आवेदन को अनुमति दी। राजस्व न्यायाधिकरण ने पुनरीक्षण में उप-कलेक्टर के इस आदेश की पुष्टि की।

अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया था किः (1) विभाजन हिंदू कानून के प्रावधानों के विपरीत था; और (2) यह मानते हुए भी कि 29 जून, 1959 का विभाजन विलेख एक वैध दस्तावेज था, इसे नजरअंदाज करना पड़ा क्योंकि यह बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, 1958 की धारा 38 (7) के प्रावधानों को देखते हुए प्रत्यर्थी को स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं कर सकता था। हालांकि उच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निचली अदालतों के समक्ष जो किया गया था वह एक पारिवारिक समझौता था।

अपील को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय, पकड़नाः (1) संपत्ति का विभाजन केवल इनके बीच हो सकता है -

ऐसे पक्षकार जिनके पास संपत्ति पर पहले से अधिकार है। हिंदू कानून के तहत, एक महिला, बड़ी या नाबालिग का पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है। एक महिला को स्व-अर्जित संपत्ति में एक हिस्सा दिया जाता है।

पति या पिता, या संपत्ति के विभाजन के बाद सह-आंशिक संपत्ति में पति या पिता के हिस्से में। इसलिए, कोई विभाजन नहीं हो सकता है और इसलिए पैतृक संपत्ति के संबंध में एक पारिवारिक समझौता तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि यह संयुक्त है, पत्नी या बेटी के पक्ष में। [70सी-डी]

(2) संशोधन के बाद धारा 38 (7) के तहत प्राप्त होने वाली स्थिति

1963 का अधिनियम यह है कि 1 अगस्त 1953 के बाद विभाजन के माध्यम से या अन्यथा भूमि के किसी भी हस्तांतरण का हस्तांतरणकर्ता को उस किरायेदार की किरायेदारी को समाप्त करने का अधिकार प्रदान करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो एक संरक्षित पट्टेदार था और जिसका अधिकार इस तरह के हस्तांतरण या विभाजन से पहले अस्तित्व में आया था। यह संशोधन स्वीकार्य रूप से पूर्वव्यापी है। [71 जी-एच; 72 ए]

(3) अपीलार्थी 1 अगस्त 1953 से पहले से ही किरायेदार था और

वह भी 1 अप्रैल, 1961 तक ऐसे किरायेदार बने रहे। इसलिए वह 1 अप्रैल, 1961 को और उससे अधिनियम की धारा 46 के तहत एक वैधानिक मालिक बन गए। इसलिए 1962 में इस आधार पर उसे बेदखल करने की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी कि वह एक किरायेदार था और इसलिए, किराए के बकाया में गिर गया था। [72 सी-डी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 735 /1975

बॉम्बे के 21.6.1974 दिनांकित निर्णय और आदेश से

विशेष में उच्च न्यायालय। सिविल एप्प्लन। 1971 का सं. 15।

अपीलार्थियों के लिए यू. यू. ललित और ए. जी. रत्नपर्खी।

प्रतिवादी के लिए एम. एस. गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

SAWANT, J. ये कार्यवाही बॉम्बे के तहत उत्पन्न होती हैं।

किरायेदारी और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, 1958 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित)। अपीलार्थी हीराजी तोलाजी स्वीकृत रूप से गाँव माढा, तालुका चिखलिया जिला बुलढाना के सर्वेक्षण संख्या 30 के रूप में कृषि भूमि का एक संरक्षित पट्टेदार या किरायेदार था। यह भूमि लगभग 25 एकड़ और 31 गुंठा में फैली हुई है। प्रतिवादी जो मानसिक रूप से विकलांग है, काफी विषम परिस्थितियों में विचाराधीन भूमि

की मकान मालकिन बन गया, जो कम से कम कहने के लिए कानून में अक्षम्य हैं। उनके पिता श्री बृजलाल बंसीलाल के स्वामित्व में थे।

लगभग 568 एकड़ भूमि जिसमें सूट भूमि एक हिस्सा है। माना जा सकता है कि ये जमीनें पैतृक हैं। उन्होंने 31 जनवरी, 1949 को अपनी पूरी भूमि का पहला विभाजन एक ओर अपने और दूसरी ओर अपनी पत्नी और एक नाबालिग बेटे के बीच किया। 16 दिसंबर, 1950 को उन्होंने एक ओर अपने और दूसरी ओर अपनी पत्नी और अपने बेटे के बीच उन्हीं भूमि का दूसरा विभाजन किया। 29 जून, 1959 को फिर से उन्होंने एक ओर अपने और दूसरी ओर अपनी पत्नी और अपनी दो नाबालिग बेटियों के बीच उक्त भूमि का तीसरा विभाजन किया। आगे इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इस तीसरे विभाजन में ही वाद भूमि प्रत्यर्थी के हिस्से को दी गई थी और प्रत्यर्थी कथित विभाजन की तारीख से कथित मकान मालकिन बन गया था।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि 1962 में किसी समय, प्रत्यर्थी उनके माध्यम से संरक्षक, अर्थात् उसके पिता बृज लाल ने अपीलार्थी के खिलाफ तीन साल के लिए किराए के भुगतान में चूक के आधार पर वाद भूमि के कब्जे की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की, अर्थात् 1959-60,1960-61 और 1961-62। 30 अप्रैल, 1963 के अपने फैसले से तहसीलदार ने यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी मकान मालकिन नहीं था क्योंकि विचाराधीन विभाजन अवैध थे। अपील में डिप्टी कलेक्टर ने 26 नवंबर, 1963 के अपने आदेश द्वारा उक्त निर्णय की पुष्टि की। महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादी का संशोधन भी विफल रहा जब न्यायाधिकरण ने 29 अप्रैल, 1965 के अपने फैसले से इसे खारिज कर दिया। अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में

227 संविधान के तीन अधिकारियों के उक्त निर्णय के खिलाफ, उच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर, 1966 के अपने आदेश द्वारा विभाजन की वैधता की जांच के लिए मामले को तहसीलदार को भेज दिया।

3. इसके बाद मुकदमे का दूसरा दौर शुरू हुआ। रिमांड पर,

तहसीलदार ने 16 मार्च, 1968 के अपने निर्णय में कहा कि 29 जून, 1959 को हुआ विभाजन (जहां तक प्रत्यर्थी का संबंध है, यह एकमात्र भौतिक विभाजन था) फर्जी था। इसलिए मांग की सूचना और इसलिए उसके अनुसार कब्जे की वसूली के लिए कार्यवाही, कानून में खराब थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद एक अलग कार्यवाही में महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण ने 25 जून, 1968 को निर्णय दिया था कि उक्त विभाजन बाध्यकारी था। न्यायाधिकरण के इस निर्णय के बाद, जैसा कि पहले एक पूरी तरह से अलग कार्यवाही में कहा गया था, यह मामला 2 मार्च, 1968 को तहसीलदार के फैसले के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा डिप्टी कर्नल कलेक्टर के समक्ष दायर अपील में सुनवाई के लिए आया था। इसलिए, उप-कलेक्टर ने राजस्व न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय का पालन किया और 16 अप्रैल, 1969 के अपने निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि विभाजन वैध होने के कारण, प्रत्यर्थी वाद भूमि की मकान मालकिन थी और इसलिए, उसके द्वारा दिया गया नोटिस, किराए के चूक के आधार पर किरायेदारी को समाप्त करना और वाद भूमि की वसूली के लिए दायर कार्यवाही उचित थी। उन्होंने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी तीन साल के लिए किराए के बकाया में था जैसा कि प्रतिवादी ने तर्क दिया था और इसलिए, अपीलार्थी को वाद भूमि से बेदखल करने के लिए उक्त आवेदन को अनुमति दी।

उक्त निर्णय के विरुद्ध, अपीलार्थी ने एक संशोधन को प्राथमिकता दी राजस्व न्यायाधिकरण और न्यायाधिकरण ने 15 सितंबर, 1970 के अपने फैसले से उप-कलेक्टर के निष्कर्षों की पुष्टि की।

निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने एक रिट याचिका को प्राथमिकता दी संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष और उच्च न्यायालय ने 21 जून, 1974 के अपने विवादित फैसले से याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए यह अपील की गई है।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष, दो स्पष्ट अवैधताएँ अपीलार्थी की ओर से निचले अधिकारियों पर प्रकाश डाला गया। पहली अवैधता यह थी कि संपत्ति पैतृक होने के कारण, बृजलाल एक ओर अपने और दूसरी ओर अपनी पत्नी और बेटी के बीच संपत्ति का

विभाजन नहीं कर सकते थे। इन सबमें 31 जुलाई, 1949,16 दिसंबर, 1950 और 29 जून, 1959 को प्रभावी तीन विभाजन, पत्नी विभाजन के पक्षों में से एक थी। 29 जून, 1959 को हुए तीसरे विभाजन में उनकी पत्नी के अलावा, विभाजन के अन्य पक्षकार दो नाबालिग बेटियाँ थीं। दूसरा, यही संपत्ति बृज लाल द्वारा तीन मौकों पर विभाजित की गई थी। मान लीजिए कि 29 जून, 1959 का विभाजन एक ओर बृज लाल और दूसरी ओर उनकी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों के बीच है। यह विभाजन स्पष्ट रूप से हिंदू कानून के प्रावधानों के विपरीत था। अतः प्रत्यर्थी किसी भी मामले में वाद भूमि की मकान मालकिन नहीं बन सकता था क्योंकि 29 जून, 1959 के इस तीसरे विभाजन में कथित रूप से उक्त भूमि प्रत्यर्थी के हिस्से में चली गई थी। उच्च न्यायालय ने पेटेंट की अवैधता के संबंध में इस तर्क को एक विशाल कारण देते हुए खारिज कर दिया कि प्रश्न [1990] 1 एस. सी. आर. तहसीलदार को उसके पहले के रिमांड आदेश में संदर्भित किया गया था, अर्थात् विभाजन की वैधता या अन्यथा, तीनों द्वारा जांच की गई थी।

अधिकारियों और उन्होंने विभाजन को बरकरार रखते हुए एक निष्कर्ष दिया था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि निचली अदालतों के समक्ष जो प्रस्तुत किया गया था वह एक पारिवारिक समझौता था और चूंकि उक्त पारिवारिक समझौते ने प्रतिवादी के पक्ष में अधिकार पैदा किया था, इसलिए उसे वाद भूमि का मालिक माना जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि विभाजन के बदले में अदालतों द्वारा स्वीकार किया गया पारिवारिक समझौता एक ऐसा समझौता है जो पक्षकारों को उनकी कानूनी पात्रता के अनुसार हिस्सा देता है, न कि एक समझौता जो कानून को दरकिनार करने के लिए किया गया है या किया गया है। संपत्ति का एक पक्ष केवल उन पक्षों के बीच हो सकता है जिनके पास संपत्ति पर पहले से अधिकार है। हिंदू कानून के तहत, एक महिला, बड़ी या नाबालिग का पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है। एक महिला को पति या पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में, या संपत्ति के विभाजन के बाद पति या पिता के हिस्से में एक हिस्सा दिया जाता है। इसलिए, कोई विभाजन नहीं हो सकता है और इसलिए पैतृक संपत्ति के संबंध में एक पारिवारिक समझौता तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि यह संयुक्त है, पत्नी या दोनों में से किसी एक के पक्ष में।

बेटी। चूंकि इस स्पष्ट अवैधता को उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, इसलिए यह मानना होगा कि उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से गलत था। इसलिए, प्रत्यर्थी कभी भी भूमि का मकान मालकिन नहीं बना और यह बृज लाल ही था जो उसी का मकान मालिक बना रहा। इसलिए प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया नोटिस और उसके द्वारा बेदखली के लिए अपनाई गई कार्यवाही गलत है। इसलिए, भूमि पर कब्जा करने के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

5. दूसरी स्पष्ट अवैधता जो ध्यान में लाई गई थी उच्च न्यायालय का यह कहना था कि यह मानते हुए भी कि 29 जून, 1959 का विभाजन विलेख एक वैध दस्तावेज था, इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि यह अधिनियम की धारा 38 (7) के प्रावधानों को देखते हुए प्रत्यर्थी हस्तांतरणकर्ता को स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा 46 के तहत, एक संरक्षित किरायेदार 1 अप्रैल, 1961 को और उससे भूमि का मालिक बन जाता है। हालाँकि, धारा 38 (1) के तहत, एक मकान मालिक को एक किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार दिया जाता है यदि वह वास्तविक व्यक्तिगत खेती के लिए भूमि चाहता है। भूमि के कब्जे के लिए कार्यवाही अपनाने के अधिकार का प्रयोग 31 मार्च, 1961 को या उससे पहले किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस तरह के आवेदन की पूर्व शर्त यह है कि मकान मालिक को एक इस उद्देश्य के लिए किरायेदार को 15 नवंबर, 1961 को या उससे पहले नोटिस। धारा 38 (2) के तहत, मकान मालिक के मामले में कब्जे के लिए आवेदन करने का समय बढ़ाया जाता है जो नाबालिग, विधवा या किसी शारीरिक या मानसिक विकलांगता के अधीन व्यक्ति है। हम वर्तमान मामले में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चिंतित हैं जो मानसिक रूप से विकलांग है, क्योंकि प्रतिवादी पर एच. टी. बागवान बनाम आरोप लगाया गया है। मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति होना। इसके अलावा उप-धारा के लिए परंतुक

(2) धारा 38 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां ऐसा व्यक्ति संयुक्त परिवार का सदस्य है, वहां मकान मालिक को किरायेदारी समाप्त करने के लिए दिया गया समय नहीं बढ़ाया जाता है यदि संयुक्त परिवार का कम से कम एक सदस्य विकलांग व्यक्तियों की श्रेणियों से बाहर है। ऐसा विकलांग व्यक्ति,

इसके अलावा, 31 मार्च, 1961 को भूमि का मालिक होना चाहिए।

6. इन प्रावधानों का कुल कुल यह है कि अपीलार्थी यदि प्रतिवादी उस तारीख से पहले वाद भूमि की मकान मालकिन के रूप में हस्तक्षेप नहीं करता है तो वर्तमान मामला 1 अप्रैल, 1961 को और उससे वाद भूमि का मालिक बन जाएगा। मान लीजिए, प्रत्यर्थी पर 29 जून, 1959 को हुए विभाजन के कारण मकान मालकिन बनने का आरोप है। तथापि, अधिनियम की धारा 38 (7) इस प्रकार बताती हैः

" इस धारा में कुछ भी कार्यकाल धारक को प्रदान नहीं करेगा। जिसने हस्तांतरण या विभाजन के बाद किसी भूमि का अधिग्रहण किया हो। अगस्त 1953 का पहला दिन एक के किरायेदारी को समाप्त करने का अधिकार किरायेदार जो एक संरक्षित पट्टेदार है और जिसका इस तरह का अधिकार है इस तरह के हस्तांतरण से पहले संरक्षित पट्टेदार अस्तित्व में आया था फेर या विभाजन "।

यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि सरकारी प्रेस द्वारा प्रकाशित अधिनियम की कुछ प्रतियों में, अगस्त 1953 के पहले दिन के बजाय, मुद्रित तिथि अगस्त 1963 का पहला दिन है। यह निश्चित रूप से गलत है। हम.

बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स (विदर्भ क्षेत्र) (संशोधन) अधिनियम, 1963। उस संशोधन अधिनियम द्वारा, धारा 38 (7) में "स्थानांतरण" शब्द के बाद "या विभाजन" शब्दों को जोड़ा गया था। हस्तांतरण की तारीख में कोई संशोधन नहीं किया गया था जिसके बाद भूमि को अधिकार नहीं दिया जाएगा। वास्तव में, संशोधन अधिनियम में यह भी कहा गया है कि संशोधन बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के 1969 के महाराष्ट्र लॉ जर्नल पृष्ठ 933 में दिए गए निर्णय के अनुसार किया गया था, जिसमें न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि "स्थानांतरण" पर विचार किया गया था। धारा 38 (7) के अप्रमाणित प्रावधान में अंतरण शामिल नहीं था -

विभाजन। इसलिए, विभाजन द्वारा हस्तांतरण को भी "हस्तांतरण" में शामिल करना आवश्यक हो गया था और इसलिए, संशोधन अधिनियम केवल उस धारा में "हस्तांतरण

द्वारा" और "ऐसे हस्तांतरण से पहले" शब्दों के बाद "या विभाजन" शब्दों को जोड़ने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।

7. धारा 38 (7) के तहत प्राप्त होने वाली स्थिति

इसलिए, संशोधन अधिनियम 1963 यह है कि 1 अगस्त 1953 के बाद विभाजन के माध्यम से या अन्यथा भूमि के किसी भी हस्तांतरण का हस्तांतरणकर्ता को किरायेदारी को समाप्त करने का अधिकार प्रदान करने का कोई प्रभाव नहीं है।

उस किरायेदार का, जो एक संरक्षित पट्टेदार था और जिसका संरक्षित पट्टेदार के रूप में अधिकार इस तरह के हस्तांतरण या विभाजन से पहले अस्तित्व में आया था। यह संशोधन स्वीकार्य रूप से पूर्वव्यापी है। इसलिए यह मानते हुए भी कि 29 जून, 1959 का विभाजन वैध था, इसने प्रत्यर्थी को अपीलार्थी की किरायेदारी को समाप्त करने का अधिकार नहीं दिया, जो 1 अगस्त, 1953 से पहले स्वीकृत रूप से एक संरक्षित पट्टेदार था और 1 अप्रैल, 1961 को ऐसे किरायेदार के रूप में भूमि पर था।

8. इसलिए परिणाम यह है कि सबसे पहले, प्रत्यर्थी ने नहीं किया था मुकदमा भूमि की मकान मालकिन बन गई क्योंकि विभाजन में उसे दिया गया हिस्सा प्रथम दृष्टया अवैध और कानून के प्रावधानों के विपरीत था। दूसरा, यह मानते हुए कि विभाजन वैध था, प्रत्यर्थी को किसी भी आधार पर अपीलार्थी की किरायेदारी को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलार्थी 1 अगस्त 1953 से पहले से ही किरायेदार था और 1 अप्रैल, 1961 तक ऐसा किरायेदार बना रहा। इसलिए वह 1 अप्रैल, 1961 को और उससे धारा 46 के तहत एक वैधानिक मालिक बन गए। इसलिए 1962 में इस आधार पर उसे बेदखल करने की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी कि वह एक किरायेदार था और इसलिए, किराए के बकाया में गिर गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने उक्त पेटेंट कानूनी स्थिति की दृष्टि खो दी और उस ओर से विवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें शामिल प्रश्न कानून और तथ्य का प्रश्न था। हम यह देखने में असमर्थ हैं कि उक्त प्रश्न के निपटारे के लिए जाँच करने के लिए तथ्य के किन प्रश्नों की आवश्यकता थी। यह रिकॉर्ड पर स्वीकार किए गए तथ्यों से उत्पन्न होने वाले कानून का एक शुद्ध सवाल था।

9. इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर देते हैं न्यायालय और अभिनिर्धारित करें कि अपीलार्थी 1 अप्रैल, 1961 को और उससे वाद भूमि का वैधानिक स्वामी बन गया था। इसलिए, वह प्रतिवादी के हाथों बेदखल होने के लिए उत्तरदायी नहीं था और उसके द्वारा अपनाई गई कार्यवाही अवैध थी और खारिज कर दी गई थी। उत्तरदाता पूरे समय लागत का भुगतान करेगा।

आर. एस.

अपील की अनुमति दी गई।